

उत्तरांचल प्रदेश
कृषि एवं कृषि विपणन अधिनियम
अधिसूचना
08 नवम्बर, 2002 ई०

सं० 1402, कृषि/3(5)/2002-वृषिके उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल प्रदेश उत्तरांचल राज्य के संवर्धन में लागू विधि का, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में राज्य के कृषि सेवाओं को प्रेषण कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन है।

अब वृषिके उत्तर प्रदेश अधिनियम कृषि सेवा विनियमवली, 1993 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 का धारा 87 के अधीन उत्तरांचल में यथावत लागू है।

अब अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल प्रदेश में लागू करने हेतु श्री राजकपाल सिंह निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश अधिनियम कृषि सेवा विनियमवली, 1993 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत लागू रहेंगी -

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिनियम कृषि सेवा विनियमवली, 1993) अधिसूचना
एवं उपसंशोधन आदेश, 2002

- 1. उत्तरांचल प्रदेश में प्रारम्भ
- 2. उत्तर प्रदेश अधिनियम कृषि सेवा विनियमवली, 1993 के अधिनियम के अन्तर्गत उत्तरांचल प्रदेश में लागू होने पर "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा
- 3. उत्तर प्रदेश अधिनियम कृषि सेवा विनियमवली, 1993 में जोड़-बांधा शब्द "उत्तर प्रदेश" को "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा
- 4. "उत्तर प्रदेश" शब्द के अन्तर्गत उत्तरांचल के संशोधन
- 5. अधिनियम सं० 29, 2000 के अन्तर्गत उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश अधिनियम कृषि सेवा विनियमवली, 1993 में जोड़-बांधा शब्द "उत्तर प्रदेश" को "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा

संकेतः
(बि०/१०) ११०/०४
११/११/०२

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 264 of the Constitution of India, the Governor has been pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1402/Agri/3(5)/2002, dated November 8, 2002 for general information.

NOTIFICATION
November 08, 2002

No. 1402, Agri/3(5)/2002-Under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Governor is empowered to make such adaptations or modifications of the provisions of the Act as may be necessary or expedient.

Under clause (3) of Article 264 of the Constitution of India, the Governor is empowered to make such adaptations or modifications of the provisions of the Act as may be necessary or expedient.

In pursuance of the power conferred under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Governor is pleased to direct the U.P. Subordinate Service Board, 1993 to make such adaptations or modifications of the provisions of the Act as may be necessary or expedient.